

LOK SABHA

\*Friday, June 16, 1967/Jyaishta 26, 1889  
(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the  
Clock

[MR SPEAKER in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नियंत्रण हटाये जाने के बाद इस्पात का मूल्य

+

\* 541 श्री स० चं० सामन्त :

श्री राम मूर्ति .

श्री प्र० क० गोपालन :

श्री बाबूदेवन नायर :

श्री बीरेन्द्रनाथ .

श्री काशी नाथ पांडे .

श्री ईश्वर रेड्डी :

श्री मधु तिमये :

डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री जार्ज फरनेम्बीज :

श्री मोहन स्वयं :

श्री रा० स्व० बिट्ठाणी :

श्री राम कृष्ण पुट्ट :

श्री जयलाल शर्मा :

श्री जयिभाई चं० फलेस :

डा० महादेव प्रसाद :

श्री जल सिंहारी बाजपेदी :

श्री जयलाल गुप्त :

श्री बीरेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री पाचसारखी :

श्री क० हाम्बर :

क्या इस्पात, ज्ञान तथा धातु मंत्री  
यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस्पात से नियंत्रण हटाये जाने  
से इस्पात की बनी वस्तुओं के मूल्यों में कितनी  
बढ़ि हुई है तथा इसके क्या कारण हैं,

(ख) मूल्यों को बढ़ने से रोकने के  
लिये क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या देश में इस्पात का उत्पादन  
अब उस स्थिति पर पहुंच गया है कि नियंत्रण  
हटाये जाने से खुले बाजार में इस्पात के व्यापार  
में कोई कठिनाई नहीं होगी; और

(घ) क्या नियंत्रण हटाये जाने से  
पहले उनके मन्त्रालय द्वारा किये गये अध्ययन  
तथा मांगो के तुलनाओं का ब्यौटा दर्शाने वाला  
एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House [Placed in Library. See No. LT-685/67]

Shri S. C. Samanta: May I know what results are perceptible at present after the de-control of all sorts of steel from 1st May, 1967?

Shri P. C. Sethi: Actually the categories in short supply will take about 3 to 4 months to stabilise, because production in those categories is likely to rise now and the position would be easier.

**Shri S. C. Samanta:** May I know for how long Government intends to study the working of decontrol and whether any other committee will be established for that purpose?

**Shri P. C. Sethi:** There is no idea of establishing any other committee, but we would like to see the market conditions for at least a few months and then we would come to a conclusion.

**Shri Vasudevan Nair:** In the statement Government has tried to explain away the whole thing by saying,

"It is not correct, however, to say that the price increases have occurred as a result of decontrol."

But we find from the statement that the prices of all categories of steel have gone up. They have said that some items are in short supply and so there is some justification for prices going up. But what is the justification for the prices of all the items going up? May I know whether Government will seriously consider, in case this trend persists, going back on the present decision of decontrol?

**Shri P. C. Sethi:** We have said it because no increase in price was given to the steel industry since 1st March, 1964. Whether decontrol would have come or control would have remained, some price increase was due. That is why we said, there is no connection between the price increase and decontrol.

**श्री मधु लिमये :** स्टील के दामों में कुछ इजाफा अनिवार्य था कि भावकारी बर्गरह बढ़ गई थी। लेकिन इन्होंने जो तालिका दी है उस में कुछ चीजों के दाम तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं जैसे गैन्वेनाइज्ड कोरोगेटिड शीट्स 29 प्रतिशत, उसी तरह से स्टील एंड टायर्स, प्रोल्ड डिजाइन 20 प्रतिशत, कोल्ड रोल्ड शीट्स बारह प्रतिशत, एक्समज प्रोल्ड डिजाइन 21 प्रतिशत। क्या मंत्री महोदय व्यौरा देंगे कि एक्साइज

ड्यूटी बढ़ने के कारण मूल्य वृद्धि कितनी समर्थनीय थी और उससे ज्यादा कितनी हुई है? यदि ज्यादा है तो फिर एक सवाल उठता है घष्यस महोदय प्रकसर कहा जाता है, मुक्त व्यापार होना चाहिये, और मुक्त व्यापार होने से दाम गिरेंगे, यहां तो मुक्त व्यापार की इजाजत दी गई है फिर क्या कारण है कि इतने ज्यादा दाम बढ़ गए हैं। मैं पूंजीपतियों से भी जानना चाहता हूं कि आखिर मामला क्या है? क्या कारण है कि मुक्त व्यापार जब होता है तो दाम गिराने के बजाय उनको बढ़ाते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बात का मंत्री महोदय खुलामा करें।

**श्री प्र० बं० सेठी :** जहां तक एक्साइज ड्यूटी और फ्रेट का ताल्लुक है इनकी वजह से दामों में बढ़ोतरी पहले भी की जाती रही है। इस समय जो भावों में बढ़ोतरी की गई है खाम नौर से कोरोगेटिड शीट्स में, स्टीलज में और एक्सलज में उसको मैं बता देता हूं। कोरोगेटिड शीट्स में इजाफे का सब से बड़ा कारण यह है कि करीब 120 रुपये का फर्क जो जिक इस्तेमाल होता है और जो इम्पोर्ट होता है उसकी प्राइस में पड़ गया है। करीब तीस रुपये का फर्क डिबैल्युएशन की वजह से पड़ा है। इंजिनियरिंग इंडस्ट्री को कुछ एक्सपोर्ट के लिए सबसिडी भी देने वाले हैं। इन सब को देखते हुए जो इजाफा किया गया है वह बाजार के हालात को देखते हुए मुनासिब मालूम होता है।

**श्री जावं करमेश्वरी :** ये जो दाम बढ़े हैं, मैं जानना चाहता हूं कि विदेशों से जो घसग घसग किस्म का सामान अभी भी हिन्दुस्तान में आयात किया जाता है, उसके भी दामों में यह बढ़ोतरी हुई है और हुई है तो किस परिणाम में हुई है?

**श्री प्र० बं० सेठी :** यह जो बढ़ोतरी की गई है यह तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

श्रीर प्राइवेट सैक्टर का जो इंडिजीनस स्टील है, उस में की गई है।

श्री राम कृष्ण गुप्त : यह कहा गया है कि कुछ ऐसी आइटम्स हैं जिन का प्रोडक्शन जरूरत के मुताबिक नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि वे कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और उन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जिन कैटेगरीज़ को अभी शॉर्टेज है उन में खास तौर से फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं, कोरोगेटिड शीट्स हैं, प्लेट्स आदि हैं। कोरोगेटिड शॉट्स के प्रोडक्शन में इजाफा करने की कांशिश की जा रही है। इसके लिए ज़िंक के लाइसेंस दिये गये हैं। यह आशा की जाती है कि दो तीन महीने में इन चीज़ों का प्रोडक्शन पहले से बढ़ेगा। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि पूरा तरह से जो डिमांड है उसको हम मोट कर लेंगे।

श्री मणिभाई जे० पटेल : मेरे दो सवाल हैं। एक तो यह है

“(1) What effect the Government has recorded in the internal market after de-control of steel;

दूसरा यह है :

(2) how many kinds of steel are still imported from abroad and what steps the Government is taking to produce them in this country.”

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक बाजार में एन्वैनेबिलिटी का सवाल है जो फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं तथा इस तरह की दूसरी आइटम्स हैं उनकी कमी अभी भी महसूस की जा रही है। जहां तक आयात का सवाल है, दूसरा एलाय, फ्लैट्स एंड बीट्स, फ्लैट प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट की जाती हैं।

श्री धनल बिहारी बाजपेयी : क्या यह समझा जाए कि स्टील के दामों में जो वृद्धि हुई है उससे सरकार सन्तुष्ट है और दामों को कम करने के लिये कोई भी कदम उठाने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक बढ़ोतरी का सवाल है अन्य चीज़ों की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी तुलना में जे० पी० सी० ने जो प्राइसिम को इनक्रीज किया है वह संतोषजनक प्रतीत होता है। यह खयाल है कि जो बढ़ोतरी की गई है उसकी वजह से अब कम से कम एक साल तक और कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसका खयाल रखा जाएगा और बढ़ोतरी न हो, इसकी कोशिश की जाएगी।

श्री कृष्ण चन्द कश्यप : कोई गारंटी दे सकते हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : माल भर नहीं होगी, ऐसा खयाल है।

Mr. Speaker: Please sit down. Ministers should wait for the name to be called. They should not simply answer to whoever puts a question.

श्री कंबरलाल गुप्त : खास तौर से कोरोगेटिड शीट्स के मूल्यों में तथा एक्सेल्स, प्लेट डिजाइन के मूल्यों में वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है। इनके अलावा और भी चीज़ें इस लिस्ट में दी गई हैं। डिक्ट्रोल के पहले भी इनकी ब्लैक मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा थी, क्या यह बात ठीक है ? अगर ठीक है तो उस वक़्त क्या प्राइस थी और उसके मुकाबले में अब प्राइस कुछ बढ़ी है, कम हुई है या उतनी ही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : ब्लैक मार्केट प्राइस का तो ठीक से बंदाबा नहीं है। लेकिन यह कहा जाता है कि कोरोगेटिड शीट्स का

में दो हजार से लेकर पच्चीस सौ रुपये टन के भाव से मिलती थीं।

श्री कंबरलाल गुप्त : अब क्या भाव है ?

श्री प्र० चं० सेठी : ठीक पता नहीं है। ब्लैक मार्केट का तो अब सवाल नहीं है।

श्री कंबरलाल गुप्त : भाव का भाव सफेद में बता दीजिये।

श्री प्र० चं० सेठी : इसका भाव पंद्रह सौ टन के लगभग फिक्स है। लेकिन बाजार में शायद 1700-1800 के आसपास बिकती है।

Shri Virendrakumar Shah: Sir, before I put my supplementary I would like to know whether my impression about a reply given by the Minister is correct. My question is based on that. Did the Minister say that there is no connection between price increase and de-control?

Shri P. C. Sethi: I did say, Sir, that as far as price increase is concerned even without de-control it was due.

Shri Virendrakumar Shah: Thereby he means that there is no connection between price increase and de-control. De-control came into effect on 1st May and price increase was announced on 2nd May after obtaining the approval of all ministries including the Steel Ministry of which the hon. Minister is in charge. If that is so, would it be a correct statement to make that there is no connection between price increase and de-control? May I also now whether Government have received representations from processing industries like re-rolling industry and engineering industry to the effect that this increase in price is high in the sluggish market, which the Government themselves have accepted, and that this is going to act further adversely?

Dr. Chenna Reddy: The position is there is no connection between the two. The increase in price was inevitable and it was inherent in the situation since 1964 when the prices were revised. Secondly, the prices for re-rollers and billets have been increased. Along with this increase, de-control has also been effected. Regarding the increase in the price of billets, to which the hon. Member has referred, it is a fact that the increase is there. JPC has been advised to examine the matter. It is under consideration.

Mr. Speaker: I would suggest that along with S. Q. No. 542, S.Q. Nos. 545 and 558 may also be taken up.

#### Corporation for closed Textile Units †

\*542. Shri K. Ramani:  
Shri Mohammad Ismail:  
Shri Umanath:

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether some State Government have made proposals to establish a corporation to run the closed textile units taken over by Government;

(b) if so, the names of such State Governments and the main features of the proposals;

(c) whether Government have considered the proposals; and

(d) if so, the result thereof?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) Yes, Sir

(b) The Government of Maharashtra in their Fourth Plan proposals proposed the setting up of a Textile Corporation for taking over the closed mills which are capable of being salvaged. They proposed an outlay of Rs. 5 crores for investment in the share capital of the proposed Corporation.

(c) and (d). Government are, themselves, proposing to set up a Textile Corporation to take over such textile mills.

**Assistance to Textile Units****\*545. Shri Liladhar Kotoki:****Shri N. R. Laskar:****Shri Sradhakar Supakar:****Shri Ram Kishan Gupta:****Shri Shri Gopal Saboo:**

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether Government propose to give more concessions to marginal and weak textile units in addition to the increase in price of controlled varieties of cloth announced recently, and

(b) if so the main features thereof?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) and (b) No decisions have been taken so far

**Production of Textiles**

+

**\*552. Shri D. N. Patodia:****Shri R. Barua:****Shri C. C. Desai:****Shri Ramachandra Veerappa:****Shri Vishwa Nath Pandey:**

Will the Minister of Commerce be pleased to state

(a) whether it is a fact that there has been a considerable decline in the production of textile industry in the country in the post devaluation period,

(b) whether a number of textile mills in the country have been closed down during this period and many are facing closure, and

(c) if so, the measures taken to protect the interests of the textile industry?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) to (c). There has been some decline in the production of cloth and yarn since September, 1986, but production in July-December, 1986, compared favourably with that in January-June, 1986. Since January, 1987, the production has appreciably fallen, but this is mainly

because of the shortage of cotton necessitating even curtailment of machine activity

After devaluation 15 mills closed down. Taking into account 8 mills closed prior to devaluation, as at end of May 1987, 23 mills continued to remain closed. In the same period, further 25 mills were closed only for limited periods but have reopened since.

With a view to increasing production in cotton textile mills, (i) increased imports of cotton have been arranged, (ii) the compulsory extra closure of mills which was for one day a week till the middle of April, 1987, has now been reduced to one day in a fortnight, and (iii) financial assistance by way of direct loans, or guarantees for loans from financial institutions has been extended to cotton textile mills in a few cases either wholly by the Central Government or jointly with the State Governments concerned

Shri K. Ramani. In view of the statement made by the hon Minister I would like to know whether the textile units which are to be taken over by the Government under the control of the Textile Corporation to be set up will be treated as nationalised property, that is to say, property of the Government as in other undertakings in the public sector.

Shri Dinesh Singh: I would request the hon Member to be a little patient. We shall come before this House with the proposal, and that would be the time to go into it

Shri K. Ramani: May I know the policy or basis on which compensation will be paid by the Textile Corporation for the textile units which are taken over? Will it be the market value or the book value?

Shri Dinesh Singh: It is a little too early to say all these things. When the Bill comes before the House with proposals all this can be considered.

**Shri Umanath:** The other day when a similar question was asked it was stated by the hon. Minister that the Government has decided to establish a corporation and that a legislation will be brought before the end of the session. It is on record. Very recently when Government had taken over certain mills, like Narsingji Mills, Sholapur and Akola Salwatram mills, Government have reduced the dearness allowance of the workers by 33-13 per cent and reduced the strength of the workers also. When the purpose of taking over of the mills is to maintain production and employment conditions of the workers, they have done just the contrary. Now that some mills are to be taken over by Government by bringing a legislation before the end of the session for establishing the Corporation, I would like to know from the Government whether they would be prepared to assure this House that when this Corporation takes over the mills it will see to it that the entire strength as well as the service conditions of the workers existing prior to the closure will be maintained. Can I have this assurance from the hon. Minister?

**Shri Dinesh Singh:** May I clarify the position? So far as the legislation is concerned, it is to enable us to take over these mills under certain circumstances. So far as the corporation is concerned, no legislation is necessary. It will be by a proposal which will be discussed here. Regarding the question of workers and others, naturally, we are most anxious to see that the workers get a fair deal and in any Government-owned corporation there should be no apprehension that workers will be in any way at a disadvantage. So far as the assurance is concerned, anything in regard to the Corporation, with your permission, I would like to say only when the matter is being discussed here.

**Shri Vasudevan Nair:** Sir, are you satisfied with that reply?

**Shri Sradhakar Supakar:** The answers to questions Nos. 542 and 545 indicate that the Textile Corporation will take over only the dead mills but not the dying or the suffering mills. May I know whether the Textile Corporation will only work as an undertaker and not as a doctor?

**Shri Dinesh Singh:** It might also give birth to new mills.

**Shri R. Barua:** From the answers of the hon. Minister I understand two things are emerging—one is Government's taking over the mills and the other is the Corporation's coming into existence. May I know whether Government will be taking over mills which are sick and not viable or they are going to take over mills by giving necessary compensation and then evolve new patterns?

**Shri Dinesh Singh:** As I said earlier, I would beg of hon. Members to be a little patient. When I bring this proposal before the House, all those details will be given, because the point here is in relation to what kind of mills we shall take over and that will be a technical thing. We will have to define what kind of mills will be taken over. As I said, we shall not be limited only to taking over mills but we may set up new mills ourselves.

**Shri S. K. Tapuria:** It appears to me that we are trying to drive down the same old beaten up path. I would like to know from the hon. Minister whether while making these proposals they have also tried to nail down the causes of the so-called sickness in the industry. Just saying that cotton shortage or something is responsible is not enough. Do they also suggest some practical methods besides just taking over these mills which will improve them? All that we have been hearing noised about is that Government will take them over. Do they expect that Government has a magic wand? Have you nailed down any reasons for their inefficiency and

what do you think will be the remedies other than just taking over by Government?

**Shri Dinesh Singh:** The hon. Member fully knows the difficulties that are being faced by this industry. Cotton shortage is only a temporary phase, but there have been to some extent old mills which have not been renovated from time to time. Then, there has not been ploughing back; there has been mismanagement in many cases; there have not been enough resources in some cases—these are some of the basic problems. They have been gone into; there have been a number of committees on this

**Shri M. R. Krishna:** When the Government is taking over these mills, will these mills be geared up to produce special varieties of textiles for the foreign market or is it the intention of Government only to take up these mills to produce textiles which have got very keen competition in the local market?

**Shri Dinesh Singh:** They will be export-oriented as also for internal consumption.

**Shri Swell:** The Minister is very optimistic when he says that the establishment of the Textile Corporation would not only correct the ills of the textile industry but might also give birth to many more mills. He is also on record in this House as saying that one of the main reasons why the textile mills have fared badly was the shortage of cotton supply to the mills. I would like to know from the hon. Minister whether the West Asian crisis, the closing of the Suez Canal and the uncertain political conditions in U.A.R. would not affect further the supply of cotton to this country and to the mills.

**Shri Dinesh Singh:** U.A.R. is only one of the sources from which we purchase cotton. As the hon. Member may have seen in the newspapers today, it appears that U.A.R. is making a provision to continue export

and import from India from the port of Suez. Regarding the import of cotton from other countries that passes through Suez Canal, certainly, there will be some delay because of the closure of the Canal. It is a little difficult to estimate, at this stage, because we do not know for how long the Canal will be closed. But if it is closed only for a short time, there will not be much dislocation.

**Shri Bodabrata Barua:** The imported cotton as it is made available to the textile mills in India is on a rationed basis and there is a big gap in the price that actually rules in the open market which is more favourable to stronger mills. Will the Government consider the question of selling the imported cotton in auctions in the open market and utilise that money for the improvement of the textile mills?

**Shri Dinesh Singh:** It is a suggestion for action which I have to get examined.

**Shri Hem Barua:** The hon. Minister seems to be very optimistic when he says that Suez Canal may not be closed for long. But judging from the statement made by President Nasser, the Suez Canal might be closed for long and might not be reopened for navigation because he insists upon a condition that Israel must vacate the Arab territory which she occupied during the last conflict. That will take a long time. What is the basis for the optimism of the hon. Minister?

**Shri S. S. Kothari:** Any secret message from President Nasser to Mr. Dinesh Singh?

**Shri Dinesh Singh:** If it were so, it would be difficult to share with the hon. Member.

I am sorry the hon. Member, Mr. Hem Barua, did not follow me. I said that if the Canal was going to be closed for a short time, there will not be much dislocation.

**Shri Hem Barua:** What is the basis for that optimism that the Suez Canal is going to be closed for a short time? I say that is not going to be.

**Mr. Speaker:** It is not optimism; there is a big 'if'.

**श्री मधु लिमये :** अध्यक्ष महोदय, कपड़े की पैदावार बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा है कि हम तीन इलाज कर रहे हैं—एक तो रुई मंगा रहे हैं बाहर से, दूसरी चीज जो जबरन छुट्टी सप्ताह में एक दिन भी उस को पखवाड़े में एक दिन कर दिया और फिर मिलों की वित्तीय सहायता भी कर रहे हैं। पिछली बार जब यह विधेयक लाये थे तो मैंने दो सुझाव दिए थे। एक सुझाव यह था कि यह जबरन छुट्टी हटाकर मशीनों में कोई तब्दीली न करते हुए, रुई की खपत न बढ़ाते हुए काउंट बढ़ाकर दरमियानी धरसे के लिए पैदावार को बढ़ाया जाय तो क्या जाय इस पर विचार किया गया है और दूसरा सुझाव मैंने यह दिया था कि कई बड़ी मिलों के पास बहुत रुई है उस में बिरला मिल भी शामिल है। उस के बारे में मैंने कुछ चिट्ठिया भी लिखी हैं। तो क्या इन के ऊपर छापा मार कर हम इस रुई को अपने कब्जे में ले कर दूसरी मिलों को बांटने के बारे में सरकार ने पिछले छः महीनों में कोई कार्यवाही की है ?

**श्री बिनैस सिंह :** जो पहला सवाल था माननीय सदस्य का अध्यक्ष महोदय, मैंने जो उस के संबंध में लोगों से बातें कीं तो उन्होंने कहा कि भलग भलग तरह के कपड़े बनते हैं और सब कपड़ों में उस तरह से घागा मोटा करने से कपड़े के लिए अच्छा नहीं होता। भलग भलग बेराइटी का कपड़ा बनता है भलग भलग काम के लिए। . . . (जबजबान) . . . मैं तो कपड़ा बनता नहीं, अध्यक्ष महोदय।

दूसरी बात—रुई का बर्हातक सवाल है उस के लिए माननीय सदस्य जानते हैं कि

कुछ नियम बने हुए हैं। नियम है कि डार्ड महीने तक की रुई मिलें अपने पास रख सकती हैं आमतौर से। उस के अलावा कुछ लोग फिक्स्ड डेट डेलिवरी पर खरीदते हैं। आज उन के पास ज्यादा नहीं है लेकिन फिक्स्ड डेट डेलिवरी पर खरीद लेते हैं जिससे कई महीनों की सप्लाई जाती रहती है। जहां पर यह पता चलता है कि कला मिल में रुई ज्यादा है तो उस की जांच की जाती है। पिछले मन्त्रे टेक्सटाइल्स कमिशनर से मैंने बात की थी इस की खास हिदायत रखनी चाहिए कि किसी खास मिल को जो इजाजत दी है उस से ज्यादा स्टॉक उस के पास नहीं होना चाहिए। अब यह भी खबर आ रही है कि खरीद फरोक, दूसरे दूसरे नामों से होती है उस की जांच हो रही है।

**श्री मधु लिमये :** छापा नहीं मारा।

**Shri S. R. Damani:** May I know whether any survey has been made of the marginal and weak units and what is the idea of providing easy finance for their modernisation?

**Shri Dinesh Singh:** Out of approximately 600 textile mills, about 250 or so were established after Independence. They are generally speaking, apart from those which are mis-managed, in a better condition. The older ones are having greater difficulties. As I have said in the body of the statement, the question of giving them finances is being considered and is being looked into by the finance agencies.

**श्री हरकम चन्द कटवाय :** मैं यह जानना चाहता हू कि हमारे देश में लगभग 600 मिल हैं उस में से सत्ता पांच सौ मिलों की स्थिति बहुत खराब है और 75 मिल ऐसी हैं जिन का संबंध विदेशों से रुई आने का है वह चल रही हैं। सरकार इन्हें अपने हाथ में लेगी फिर भी उसमें नयी मशीन और रुई लगानी पड़ेगी तो क्या सरकार का ऐसा विचार है कि मिल वार्षिक और उच्च-



पतियों को यह सारी सहायता दे और उन की हालत ठीक हो सके और क्या उद्योग-पतियों से उन्हो ने उन के विचार लिए हैं कि उन का क्या मत है इस सम्बन्ध में ?

श्री विनेश सिंह जी हा । उन से कुछ बातें हुई हैं । मैं अध्यक्ष महोदय बम्बई फिर जाऊंगा । उन से और और लोगों से भी बात करूंगा । हम को कोई एतराज नहीं है और मिल मालिक अपनी मिलों को ठीक से चलायें और सरकार की तरफ से कोई रुकावट नहीं है । हमारी तरफ से पूरी काशिश है कि जितने तरह के उद्योग हैं वह जितनी तेजी से हो सके हमारे देश में बढें उस में हमारे देश का मला है । लेकिन किसी एक खास को बुलाकर हम कहें कि आप यह करे आप को कोई खास फेमिलिटी हम देंगे यह हमारी पालिसी नहीं है ।

#### Foreign Private Investment

T

\*543 Shri Ram Kishan Gupta  
Shri Kanwar Lal Gupta  
Shri R. S. Vidyarthi  
Shrimati Tarkeshwari Sinha  
Shri S. R. Damani

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state

(a) whether any policy has been chalked out defining the general approach to foreign private investment with a view to removing uncertainties currently inhibiting the initiative of foreign investors, and

(b) if so the broad features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Shri Bhanu Prakash Singh): (a) and (b) It is considered desirable to enumerate Government's policies on foreign collaboration and foreign investment in the form of a comprehensive Policy Statement. Details in this regard are under examination.

श्री राम किशन गुप्त मैं जानना चाहता हूँ उन मुल्कों के नाम जिन की तरफ से फारेन कॉलैबोरेशन के लिए प्रोपोजल्स आये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समन्वय-कार्य मंत्री (श्री कलकत्तीन अली अहमद) इस वक्त सब मुल्का के नाम तो नहीं दे सकता लेकिन आत रहत है और मैं मेम्बर माहब को नाम दे दूंगा ।

श्री राम किशन गुप्त मैं जानना चाहता हूँ कि फार्म एम्बेडर्स की तरफ से किस बिस्म की फर्मिलिटीज मांगी जा रही है और उन के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री कलकत्तीन अली अहमद जरा फिर शहराये, मैं ने सुना नहीं ।

अध्यक्ष महोदय श्री कवर लाल गुप्त ।

श्री कवरलाल गुप्त क्या मंत्री महोदय बतायेंगे क्योंकि इन की पालिसी जो इस क बार में है सुबह कुछ होती है, शाम कुछ होती है, एक मंत्री कुछ कहता है, दूसरा मंत्री कुछ कहता है, यहाँ कुछ कहा जाता है, कांग्रेस की मीटिंग में कुछ, और तीसरी जगह कुछ और, तो आखीरी में आपने क्या यह अपनी पालिसी बदली है ? जैसे मिनिस्टर नाहब ने कहा हम कुछ तैयार कर रहे हैं तो आप ने पहले वाली पालिसी रखी है या कुछ बदली है और बदली है तो क्या बदली है ? कौन सी बड़ी बड़ी चीजों पर विचार कर रहे हैं जो आये आप लाने वाले हैं ? दूसरी चीज—क्या विदेश के कुछ लोगों ने आप से कुछ महसूसयते मांगी हैं कि यह अगर आप हमें फर्मिलिटीज देगे तो हम अपना पैसा लगायेंगे ? अगर वह मांगी हैं तो क्या है और उन पर क्या कार्यवाही आप ने की है ?

श्री कलकत्तीन अली अहमद : जहाँ तक पालिसी का सम्बन्ध है हमारी पालिसी

1949 से जब कि इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन हम ने पास किया उस के मातहत हम ने काम किया और उसी पालिसी को हम चलाना भी चाहते हैं जैसा कि आन्तरिक मेम्बर को मालूम है कि हम ने बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए उन चीजों में सहूलियत दी जो कि हमारे मुल्क में जिन के पैदा करने में दिक्कत है जिन का टेक्निकल नो-होउ या टेक्निकल नालेज नहीं है और जिन के लिए फोरन एक्सचेंज की बहुत जरूरत है और यहाँ पैसा नहीं मिल सकता।

इस के साथ साथ हमने यह भी किया कि जहाँ तक होगा मैजोर्टी आफ शेयर्स हम लोगों का होगा और माइनोर्टी आफ शेयर्स बाहरवालों का होगा। लेकिन जन्म चीजे जैसे इंगोरेस, बैकिंग, ट्रेडिंग कार्पोरेशन वगैरह के लिये हम ने यह किया हुआ है कि वे यह हिम्मा नहीं ले सकती है। बाहर के लोगों की यह शिवायत है कि हमारी पालिसी उनको अच्छी तरह से मालूम नहीं है कि किन किन इण्डस्ट्रीज में यहाँ आ कर इन्वेस्ट कर सकते हैं, दरख्वास्त देने में उन को काफी बकन लगता है और उस के लिये किस-किस के पास जाना पड़ता है। हम इन सब बातों की डिटेल्स को देख रहे हैं, जब वे डिटेल्स तैयार हो जाएंगी, तब एक रेजोल्यूशन हमारा आयेगा। मेरा इरादा है कि पार्लियामेंट के सामने भी उस का रखना।

श्री बंजर लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया। क्या आप के पास विदेशों से कोई ऐसी माग आई है कि अगर ये सहूलियतें हम को देंगे, तब हम पैसा लायेंगे क्या उन्होंने कोई ऐसी चीज आपके सामने रखी है, यदि रखी है तो उस पर क्या धमक किया गया है ?

श्री कलचंदीन शर्मा महमद : एक शिकायत उन की तरफ से यह आई है कि जब वह हमारी कन्टी में दरखास्त देते हैं, तो उनकी बहुत बकन लगता है और कई जगह

जाना पड़ता है, इस के अलावा और कोई बात नहीं है।

श्री रा० स्व० बिश्वाची : पिछले पांच साल से लगातार फोरन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है और उस का कारण यह है कि यहाँ पर सरकार के कुछ परवरवा लोग, जिन के पास किसी ट्रेड की मोनोपोली है, वे सरकार को बाध्य करने हैं कि फोरन-एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट यहाँ न हो पाये। अगर ऐसा है, तो क्या सरकार ऐसा प्रयत्न करेगी कि फोरन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा देश में लगे और जो चीजे यहाँ पर पैदा नहीं होती हैं, वे देश की कन्ट्रिब्यूशन के लिये यहाँ पैदा हो सकें ?

श्री कलचंदीन शर्मा महमद : जैसा कि मैंने पहले अजें किया हमारी यह पालिसी है कि हम उन चीजों में फोरन इन्वेस्टमेंट मांगते हैं और सहूलियतें देते हैं, जो हम खुद अपने मुल्क में पैदा नहीं कर सकते हैं, जिनका टेक्निकल-नो-होउ या मारिनिफिकन-नो-होउ हमारे मुल्क में नहीं है। यह एक बहुत अच्छी बात है कि जब हमारे मुल्क की तरफकी हो रही है, इण्डस्ट्रीज बंद रही हैं तो लाजमी तौर पर फोरन इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और हमारे मुल्क का इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ेगा।

Shri S. B. Damani: May I know in which particular industries foreign collaboration or investment is going to be allowed and whether any list has been finalised, and if so, the names of those industries, and whether proper care will be taken to see that those plant and machinery which are manufactured in the country will not be allowed to be imported?

Shri F. A. Ahmed: As I have already pointed out, we encourage foreign investment in those industries where we lack technical know-how and where it is not possible for us to find the entire foreign exchange for the purpose.....

**Shri Kanwar Lal Gupta:** Which are those industries? The hon Minister has not named them.

**Shri F. A. Ahmed:** There is a certain banned list in which foreign investment is not allowed. If the hon. Member wants, I can lay on the Table of the House a list of the industries which are banned for the purpose of foreign investment. There are certain institutions like banking, insurance and trading institutions where we do not allow any foreign investment.

Apart from that, there are two conditions. One is that their shares should be minority shares and only in those industries where we have allowed such investment. We have allowed majority shares where the main contribution to the project is in a field of technology where India has made little progress, and secondly, the amount of foreign exchange needed for the project is such that unless the foreigner is allowed to have a majority shareholding, we shall ourselves have to find a substantial amount of it.

**Shri Vasudevan Nair:** After all this, what is left in it?

**Shri F. A. Ahmed:** These are the only two exceptions where we have accepted majority shares. Otherwise, we allow foreign investment if it is favourable to us and if we find that the development of those industries is in the interests of our country.

**Shri S. R. Damani:** My question is: in which particular line of industry foreign collaboration and investment is going to be allowed.

**Shri F. A. Ahmed:** I have said that so far as basic industries are concerned, we do not allow foreign investment. This also applies to institutions I have named, namely, insurance, banking and trading. Only where technical know-how is not available in our country and where a large volume of foreign exchange is required, and it is not possible for us to

raise that foreign exchange ourselves and also that industry is necessary for the development of our country, there we encourage and allow foreign collaboration.

**Shri H. N. Mukerjee:** In regard to majority foreign shareholding in certain instances, the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, had told this House on 2 March 1965 that Government's policy as that in cases where we are constrained to accept majority shareholding, we shall put up a condition that as far as possible ultimately they would become minority partners in the concerns which are set up. What progress has been made in this direction since 1965 and may I know whether Government intends, now that it is going to formulate a policy, to see to it that majority foreign shareholding is eliminated altogether?

**Shri F. A. Ahmed:** That is the line in which we are thinking.

**Shrimati Sharda Mukerjee:** The latest figures available according to RBI bulletins concerning the quantum of private foreign investment in 1962 come to Rs. 735 crores, which is probably 50 per cent or thereabouts of the total. With all these relaxations of rules and so on, what is the policy of Government as to the percentage of private foreign investment in regard to the total private investment in the country? What is the maximum that will be allowed?

**Shri F. A. Ahmed:** I have already said that what we have in view is the development of industries which are essential to our country and also there where technical know-how and scientific knowledge is otherwise not available. Subject to these, it is our attempt to reduce foreign investment in our country as much as possible.

**Shrimati Sharda Mukerjee:** What is the Government's policy?

**Mr. Speaker:** He has already replied to that while answering a previous question.

**Shrimati Sharda Mukerjee:** Is there going to be no limit?

**Mr. Speaker:** Shri Jha.

**श्री शिव चन्द्र झा :** मंत्री महोदय ने कहा कि फोरन इन्वेस्टमेंट के संबंध में विचार हो रहा है कि क्या पालिसी हमें बरतनी चाहिये। आज यह स्थिति है कि जिस मुल्क का प्राइवेट इन्वेस्टर यहां इन्वेस्ट करना है उस मुल्क की नीति हमारी राष्ट्रीय नीति से अन्तर्राष्ट्रीय मैदान में खिलाफ जाती है तो चाहे 50 परसेन्ट में कम भी हो, तो भारत यदि चाहे तो उस पर कब्जा कर सकता है, उस को एप्रोप्रिएट कर सकता है। मैं जानना चाहता हू कि क्या प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ से यह बात रखी जा रही है कि यदि उन के मुल्क की नीति हमारी नीति से राष्ट्रीय मैदान में खिलाफ जाती हो, तो भी 10-15 मास तक उस का एप्रोप्रिएशन नहीं होगा ?

**श्री कलशवीर शर्मा ग्रहसब :** मैंने कहा है कि हमारा सब से पहला मकसद यह है कि कन्ट्री का डेवेलपमेंट हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए जिन इण्डस्ट्रीज की हम को जरूरत है, हम उन को जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहते हैं। जिन चीजों की टैक्नीकल नो-हाऊ और फारेन एक्सचेंज की हम को जरूरत है, सरकार उन चीजों के फोरन इन्वेस्टमेंट को सहूलियत दे रही है। लेकिन जब हम अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे, हमारे पास टैक्नीकल नो हाऊ होगा, तब हम को बग़ा से रुपया लेने या टैक्निकल-नो-हाऊ लेने की जरूरत नहीं होगी।

**श्री मकीसाई खे० पंडित :** माननीय अध्यक्ष, मैं आप की मार्फत माननीय मंत्री से पूछना चाहता हू कि कौन कौन से उद्योगों में कितने कितने प्रतिशत विदेशी पूँजी लगाने पर उन्होंने मंजूरी दी है ? मंत्री महोदय कृपया उन के नाम बतलायें। दूसरे कितने

समय के अन्दर विदेशों से जो यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं उन को आप सारी सुविधाएं देते हैं और वह फैक्टरियां चालू हो जाती हैं ?

**श्री कलशवीर शर्मा ग्रहसब :** जहाँ तक इण्डस्ट्रीज के नामों कातालुक है मेरे पास इस वक्त नाम नहीं हैं बाकी अगर आनरेबुस मेम्बर को जरूरत होगी तो मैं बाद में उन्हें दे सकूंगा।

**Shri Jyotirmoy Basu:** Mr. T. T. Krishnamachari, who was once the Commerce Minister and then Finance Minister, while addressing the Associated Chamber of Commerce, Calcutta, in early 1950 had made a policy declaration that we shall only allow foreign capital to come where it is a must for technical knowhow, and for others it will be left to the sons of the soil. In view of that, may I ask the Government to tell us how far they have deviated from that policy declaration in the past, and what they propose to do for the future?

**Mr. Speaker:** He has answered. The questions are becoming repetitive.

**Shri F. A. Ahmed:** I have explained the policy we have been pursuing.

**Shri K. Narayana Rao:** The hon. Minister has pointed out that there are two factors which enter into the policy, know how and foreign exchange. So far as the foreign exchange problem is concerned, is it not true that the foreign capital has been allowed on the ground of foreign exchange, then the entire foreign exchange has again to be ploughed back by means of profit in due course of time? Such being the case, does it not mean that the foreign exchange problems of today are only deferred to the future in view of this particular thing? If so, may I know whether the Government has taken any precautionary steps in entering into these agreements to see that the profits which

ultimately the foreign investor gets will be utilised for the Indian economy itself?

**Shri F. A. Ahmed:** So far as the question of foreign exchange is concerned, the hon. Member must bear in mind that we only allow such foreign exchange to come in with respect to capital equipment which is not available in our country, and which we require immediately for the purpose of development, and only in those cases the question of foreign exchange is taken into consideration. And whenever these agreements are entered into, we try to safeguard the interests of the country so that as much as possible the profits earned here do not go out of our country.

**Shri S. S. Kothari:** Is the investment climate considered satisfactory by the Government? How does the return on capital invested in this country compare with the return on capital invested in other countries?

**Mr. Speaker:** Wider, much wider question.

**Shri F. A. Ahmed:** It is a question of opinion.

**Shri Umanath:** They have the assessment. In fact, so many times it has been mentioned. The highest return is in this country.

**Shri F. A. Ahmed:** What I am pointing out is that it is a matter of opinion. That is a question which the investor has to consider and not myself.

**Shri Umanath:** You have not considered it, the Government has not considered it?

**Shri Hem Barua:** May I know if it is a fact that the hon. Minister has decided to invite foreign capital, of course from some East European countries, for the purpose of setting up a plant in this country to manufacture small cars? If he has done so, I would like to know.

**Mr. Speaker:** How does it arise here?

**Shri Gopalan:** It has been reported that the rate of profit earned from British and American investment in India is the highest in the world as compared to the rate of profit earned in other countries. In view of this, may I now from the Minister what steps they are proposing to take to check this drain of national wealth?

**Shri F. A. Ahmed:** We examined all these proposals and we find that the agreements are in our favour; then only they are accepted. We do not in every case know what profit is earned by them in other countries and perhaps in many countries the profits earned is less or more than what they are getting in India. . . .  
(Interruptions)

**Mr. Speaker:** Next question—544.

#### Incentives for Small-Scale Sector

+

- \*544. **Shri Sharda Nand:**  
**Shri Bharat Singh Chauhan:**  
**Shri Ranjit Singh:**  
**Shri N. R. Laskar:**  
**Shri Sradhakar Supakar:**  
**Shri Liladhar Kotoki:**  
**Shri Shri Gopal Saboo:**  
**Shri A. B. Vajpayee:**  
**Shri Kanwar Lal Gupta:**  
**Shri Ram Avtar Sharma:**  
**Shri Parkash Vlr Shastri:**  
**Shri Shiv Kumar Shastri:**  
**Shri Y. S. Kushwah:**

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether Government propose to give incentives and facilities to small scale sector in order to hold the price line of consumer goods and to compete in foreign markets;

(b) whether Government have set apart 50 to 60 items of manufacture exclusively for the small scale sector; and

(c) if so, the main features of the proposals and the number of small